

Dated 26/06/2024

To,  
The Hon'ble Governor  
Government of Uttar Pradesh  
Lucknow

Through,  
The Ld. Registrar General  
The Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad  
Prayagraj

**Subject: Request of being granted lien over the post of Civil Judge (Junior Division)**

Respected Sir/ Madam,  
I am most honored to submit that I joined the Uttar Pradesh Judicial Services on 5<sup>th</sup> January 2024, after having secured Rank 4 in UP PCS (J) 2022 examination, vide Hon'ble High Court's notification No. 4/ Admin. (Services)/ 2024. I am presently serving as Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh.

It is also humbly submitted that during the course of appearing for UP PCS (J) 2022 examination, I had also applied for Civil Services Examination, 2023 conducted by the Union Public Service Commission, New Delhi. After joining the UP Judicial Services, I sought the permission from the Hon'ble Court for appearing in the interview of the Civil Services Examination, 2023. The Hon'ble Court was pleased to grant the NOC (No Objection Certificate) dated 16 February, 2024 [Annexure No. A]. Pursuant thereto, I have been selected in the Civil Services Examination, 2023 after having secured Rank 534 vide the results dated 16 April, 2024 [Annexure No. B] and am expecting allocation to IAS (Indian Administrative Services).

The reasons for requesting lien in the UP Judicial Service is set forth below:  
In the early stages of career and at my age (presently, 23 years), it is imperative that true interests towards public service be understood. It is only after having served in a service a true estimation can be gauged as to one's calling. Further, I request your esteemed self to take into account my educational background. I have graduated from the most premier law institution in the country (National Law School of India University, Bangalore) and have been recognized at different national and international forums (including Oxford University Press, International Editorship at Cambridge Law Review, among others) for my works in legal field (A full account enclosed in Annexure No. D). Sir/ Madam, I shall be an asset to the service and will put in my best to serve the mandate of law in the event of grant of relieving.

As my appointment in UP Judicial Services is temporary until absorption, attention of your esteemed self may also be drawn to page 36 of वित्त पथ, 2022 whereby lien is defined as per उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायिकरण नियमावली, 1991, प्रस्तर 3 (छ) as, “‘धारणाधिकार’ का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को (substantively a regular post) चाहे वे स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरंत या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने का अधिकार या हक से है। (Emphasis supplied); and also to page 39 of वित्त पथ, 2022 which mentions, “कार्मिक – 4 अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 1648/ 47 – का – 4-90-48/ 79 दिनांक 7-2-91 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायिकरण नियमावली प्रकाशित की गयी। इसके अनुसार सेवा शर्तों में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था कर दी गयी कि अस्थायी पद के सापेक्ष भी स्थायिकरण किया जा सकता है तथा उन सेवकों का धारणाधिकार अस्थायी पद पर हो जाएगा। (Emphasis supplied) [Annexure No. C]

Grant of such a permission from your esteemed self will also motivate and attract best talents in the country towards judicial service. Experiences gained from serving in civil services will enhance my idea of governance and expose me to its ground realities which will better help in dispensation of justice through judicial service. I shall also be deeply grateful for opportunities and guidance, which I have received in UP Judicial Services. The experience will continue to guide me in my future endeavors. I am thankful to the Judicial Training and Research Institute (JTRI), Lucknow for enlightening the legal acumen in me.

In the light of the above request, most humbly, I pray your good self to grant me lien over the UP Judicial Services. I shall be highly obliged for your kind consideration.

Thanking you!

Yours Sincerely,

*Snehil*  
26/06/2024

Snehil Kunwar Singh

Additional Civil Judge (Junior Division),

Azamgarh



**[Annexure No. A]**

**NO-OBJECTION CERTIFICATE**

It is certified that the Hon'ble High Court has 'No Objection', if Sri Snehil Kunwar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh appears in the Interview of Civil Services Examination 2023, conducted by Union Public Service Commission.

Date

*Pankaj*  
16/06/24  
(Pankaj Jaiswal)  
H.J.S.

Registrar (Judicial) (Budget)  
High Court of Judicature at  
Allahabad

**Registrar  
(Judicial) (Budget)  
High Court, Allahabad**

*Snehil*  
26/06/2024

# [Annexure No. B]

- 12 -

## CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2023

S.NO.	ROLL NO	NAME
487	6210733	ADUSUMILLI MONICA
488	0856301	PATOLIYA RAJ BHIKHUBHAI
489	6420991	HARSHVARDHAN PANDEY
490	0106438	DESAI JAINIL JAGDISHBHAI
491	1136687	MATENDRA KUMAR MEENA
492	6607547	SWATI MOHAN RATHOD
493	5104398	DONAKA PRUDHVI RAJ KUMAR
494	0818520	AJAY MOKTAN
495	1115543	SURBHI JAIN
496	0600672	PATIL LOKESH MANOHAR
497	2206857	SUDHIR PRATAP SINGH CHARAN
498	0414249	DIVYA YADAV
499	6309798	NAVNEET ANAND
500	4005986	KRISHNAKUMAR G
501	5810634	AMIT KUMAR
502	1220936	RAHUL V GOPAL
503	4105030	ADITYA KESHRI
504	0509633	RAHUL KUMAR
505	0825084	PRINCE BABU MISHRA
506	0107322	GOHIL KANCHANBEN MANSINHBHAI
507	1905195	ABDUL FASAL P V
508	0627108	KSHETRIMAYUM DEEPI CHANU
509	4115712	HIMANSHU LAL
510	0909210	KIRTI YADAV
511	6419451	ASHISH VERMA
512	0844804	MOHAMMAD AFTAB ALAM
513	5606279	SATHYANANDHI G
514	1215532	ANJALI SU GA
515	0413430	RAJAT TRIPATHI
516	3408265	SEERAT BAJI
517	1123530	DEVESH PARASHAR
518	1134566	DEEPAK YADAV
519	0816252	SHREYA SHAKYA
520	5810839	RITWIK MEHTA
521	0225602	HARSHIT SRIVASTAVA
522	1907917	SWATHI S BABU
523	6616832	BHAMARE SAGAR SANJAY
524	5803647	MAHIMA TOMAR
525	1543028	UTKARSH ROY
526	0304214	K SREENIVASULU
527	5901689	RAGHVENDRA SHARMA
528	5605156	U VIBUKRISHNA
529	1903429	SHILJA JOSE
530	2200616	SHIVANK CHOWDHARY
531	6602571	SAKORE MANASI NANABHAU
532	5205355	PRAVEEN SINGH CHARAN
533	0507442	PATIL NEHA NANDKUMAR
534	6116564	SNEHIL KUNWAR SINGH
535	6609165	YUGAL KAPSE
536	0300326	RANU GUPTA
537	1103180	GYANENDRA BHARTI
538	3904364	SATISH SHRISHAIL SOMJAL
539	0507980	MAHAJAN HARSHAL RAJESH
540	6410713	AVINASH CHOUDHARY

*Snehil*  
26/06/2024



[Annexure No. C]



# वित्त - पत्र

वर्ष 2022 अंक

*Suchil*  
26/06/2024

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन  
वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०

- (6) **मानदेय (Honourarium)**— वह आवर्तक या अनावर्तक भुगतान जो किसी सरकारी कर्मचारी को यदाकदा किये जाने वाले किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की संघित निधि या भारत की संघित निधि से पारिश्रमिक के रूप में दिया जाय। (मूल नियम 9(9))
- (7) **कार्यभार ग्रहण काल**— नये पद पर कार्यभार संभालने के लिए तथा तैनाती के स्थान तक यात्रा में लगने वाले समय को कार्यभार ग्रहण काल कहते हैं। (मूल नियम 9(10))
- (8) **औसत वेतन पर अवकाश**— का तात्पर्य औसत वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर विनियमित किये गये अवकाश से है। (मूल नियम-9(11))
- (9) **अवकाश वेतन**— अवकाश वेतन का तात्पर्य अवकाश के विषय में सरकारी कर्मियों को सरकार द्वारा किये गये मासिक भुगतान से है। (मूल नियम-9(12))
- (10) **धारणाधिकार (Lien)**— किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी स्थायी पद को मौलिक रूप से धारण करने के अधिकार को धारणाधिकार कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी स्थायी पद को या तो तुरन्त अथवा उसकी अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों के समाप्त होने पर मौलिक रूप से ग्रहण करने के अधिकार से है। इसमें वह सावधि पद (टेन्चर पोस्ट) भी सम्मिलित है, जिस पर वह मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो। (मूल नियम 9(13))
- उ0 प्र0 राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के प्रस्तर-3 (छ) के अनुसार 'धारणाधिकार' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद (substantively a regular post) को चाहे वे स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार या हक से है। *Suehil* 26/06/2024
- (11) **स्थानीय निधि (Local Fund)**— ऐसे निकाय जो विधि या विधि के समान प्रभावी नियम के अधीन शासन के नियंत्रणाधीन हो, प्रशासित राजस्व, चाहे वे समान्यतया किसी कार्यवाही या विशिष्ट मामले से सम्बन्धित हों, जैसे उनके आय-व्ययक स्वीकृत करना, किसी विशेष पद को सृजित और उस पर नियुक्ति करना या अवकाश-पेंशन अथवा इसी प्रकार के अन्य नियमों का अधिनियमन; और किसी भी निकाय के ऐसे राजस्व, जिसको सरकार ने विशेष विज्ञप्ति द्वारा स्थानीय निधि घोषित किया हो। (मूल नियम-9(14))
- (12) **लिपिक वर्गीय कर्मचारी (Ministerial Servant)**— अधीनस्थ सेवा के वे सरकारी कर्मचारी, जिनकी ड्यूटी पूर्णतया लिपिकीय है तथा किसी दूसरे वर्ग के सरकारी कर्मचारी, जिनको शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस वर्ग का घोषित कर दिया जाय। (मूल नियम 9(17))
- (13) **मास**— महीनों तथा दिनों में दी गयी किसी भी अवधि का निकालने के लिये पहले पूरे पूरे माह गिने जाने चाहिए तथा बचे हुए दिनों की संख्या बाद में गिनी जायेगी। (मूल नियम 9(18))
- (14) **स्थानापन्न (Officiate)**— कोई सरकारी कर्मचारी स्थानापन्न रूप से तब कार्य करता है जब वह उस पद की ड्यूटी करता है जिस पर दूसरे व्यक्ति का धारणाधिकार (लियन) हो। किन्तु यदि सरकार उचित समझे तो वह एक सरकारी कर्मचारी को ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार (लियन) न हो। (मूल नियम 9(19))
- (15) **वेतन**— वह धनराशि जो सरकारी कर्मियों प्रति मास पाता है— (मूल नियम-9(21))
- (1) उसकी व्यक्तिगत अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत वेतन को छोड़कर जो भी वेतन उस पद के लिए स्वीकृत किया गया हो, जिस पर वह या तो स्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्त हो और जिसको वह संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण पाने का अधिकारी हो,



- (v) स्थायी या विशेष चिकित्सा परिषद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा परन्तु यदि प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर शासन संतुष्ट हो कि पहले चिकित्सा परिषद के निर्णय में कुछ त्रुटि की संभावना है, तो शासन को दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। (सहायक नियम 15-क)

(ख) सरकारी सेवक का पूर्ण समय सरकार के अधीन :- (मूल नियम 11)

जब तक कि किसी मामले में स्पष्ट रूप से अन्यथा कोई व्यवस्था न की गयी हो, सरकारी कर्मचारी का पूर्ण समय सरकार के अधीन है और आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वह किसी प्रकार की सेवा में किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसके लिए वह अतिरिक्त पारिश्रमिक के लिए दावा नहीं कर सकता, चाहे उससे जिस भी प्रकार की सेवा ली जाये। मानदेय स्वीकृत करने के आदेशों में इस आशय का उल्लेख करना पडता है कि इस नियम की व्यवस्थाओं को यथावश्यक दृष्टिगत रखते हुए यह मानदेय स्वीकृत किया जा रहा है।

(ग) पद पर नियुक्ति :-

- (i) दो या उससे अधिक सरकारी कर्मचारी एक ही समय में एक ही स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किये जा सकते। (मूल नियम 12 (क))
- (ii) केवल अस्थायी प्रबन्ध को छोड़कर कोई सरकारी कर्मचारी दो या उससे अधिक पदों पर एक ही समय में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। (मूल नियम 12 (ख))
- (iii) किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार हो। (मूल नियम 12 (ग))

12-क. जब तक कि किसी मामले में इन नियमों में अन्यथा कोई व्यवस्था न की गयी हो, किसी सरकारी कर्मचारी के किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर उस पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त हो जाता है और दूसरे पद पर उसका पहले से प्राप्त किया हुआ धारणाधिकार समाप्त हो जाता है।

(घ) धारणाधिकार (लियन) संबंधी प्रावधान :-

- (i) कार्मिक-4 अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 1648/47-का-4-90-48/79 दिनांक 7-2-91 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 प्रकाशित की गयी। इसके अनुसार सेवा शर्तों में अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था कर दी गयी कि अस्थायी पद के सापेक्ष भी स्थायीकरण किया जा सकता है तथा उन सेवकों का धारणाधिकार अस्थायी पद पर हो जायेगा।

*Snehil*

(मूल नियम 13) 26/06/2024

(ii) धारणाधिकार कब तक -

जब तक किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार नियम-14 के अन्तर्गत निलम्बित अथवा नियम 14-ख. के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता उस पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है-

(क) जब तक वह उस पद की ड्यूटी करता रहे।

(ख) जब वह बाह्य सेवा में हो या किसी अस्थायी पद पर नियुक्त हो या किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो।

SNEHIL KUNWAR SINGH

[Annexure No. D]

Rank 534 | Expecting IAS 2024 Batch, UPSC Civil Services Examination 2023]

Rank 4, UP Judicial Services 2022

B.A. LL.B. (Hons.) NLSIU Bangalore

International Editor, Cambridge Law Review

#### ACADEMIC PROFILE

National Law School of India University, Bangalore

(2017 – 2022)

B.A.LL.B. (Hons.) (CGPA 5.12/7.00) [Highest Grade 'O' (Outstanding) in Constitutional Law, CPC, Law of Contracts, Law and Economics, Clinical Course]

The Frank Anthony Public School, New Delhi (ISC)

(2016 – 2017)

Council for the Indian School Certificate Examination (Class 12) – 96.75% (*Delhi Topper, Top 1 percentile of ISC, 2017*)

St. John's School, Jaunpur, Uttar Pradesh (ICSE)

(2007 – 2015)

Council for the Indian School Certificate Examination (Class 10) – 95.20% (*District Topper*)

#### Other Relevant Courses

Academic Support Programme, NLSIU; Electronic Database Workshop on SCC Online, Manupatra, LexisNexis and Westlaw (2017)

#### PUBLICATIONS AND RESEARCH WORK

- Telecast Bans of Television News in India: Issues and Reform, *Indian Law Review* (Taylor & Francis).
- Pre-Constitutional Laws in India: Beyond Presumption of Constitutionality, *Statute Law Review* (Oxford University Press). (2020)
- Panoptic Jurisprudence of a Big Brother State: Surveillance and Privacy vis-à-vis Section 69 of the Information Technology Act, *GNLU Law and Society Review*. (2020)
- How can the Judiciary's ability to dispense justice be improved, *Economic and Political Weekly*, Vol 54 Issue No. 44. (2019)
- 'Ordinance Raj': Bypassing democracy through Executive's Backdoor, *RMLNLU Constitutional Law and Public Policy Blog*. (2019)
- Intragroup dissent & Sabrimala, *Journal of Indian Law and Society Blog [NUJS]* (co-authored by Bhaskar Kumar). (2018)
- Religious Practices and Evolving Jurisprudence of Article 17, *Journal of Indian Law and Society, Vol VIII [NUJS]*. (2017)
- Member, Research Team at **LiveLaw**.
- Columnist, **The Telegraph** [Upon invitation]
- Columnist, **The Quint**.
- Columnist, **The Wire**.

Snehit  
26/06/2024



## [Annexure No. D]

- Columnist, **Deccan Herald**.
- Columnist, **Firstpost**.
- Research Assistant to Prof Arpan Banerjee, Executive Director, Centre for IP & Technology Law, Jindal Global Law School. (February 2020)
- Researcher, Team on Repeal of Laws at Centre for Civil Society. (September 2019)
- Researcher, Team on Simplification of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 at Finsec Law Advisors. (July 2018 – October 2018)

### ACHIEVEMENTS

#### Moot

Speaker, 2<sup>nd</sup> Justice Y.K. Sabharwal Constitutional Law Moot Court Competition, 2019 at NLU Delhi – Qualified Memorial Qualifier Rounds for Top 12 teams. (November 2019)

#### Other

Speaker, Session on Academic Legal Writing, by Savitribai Phule Ambedkar Caravan, NLSIU (2020)  
Winner, 4<sup>th</sup> GNLU Essay Competition on Law and Society (2019)  
Runner-up, 1<sup>st</sup> Adv. Vijayaraghavan Memorial Essay Competition organised by School of Legal Studies, Cochin University (2019)

### POSITIONS OF RESPONSIBILITY

- **Blind Peer Reviewer**, Economic and Political Weekly (Upon Invitation)
- **International Editor**, Cambridge Law Review (Upon Invitation)
- **Reviewer**, Screening Board, Essay Competition by The Dialogue and Law and Technology Society, NLSIU Bangalore
- **Editor**, National Law School of India Review
- **Member**, Student Advocate Committee, NLSIU
- **Reviewer**, Essay Competition on “Domestic Violence – The Shadow Pandemic”, Organised by Law and Society Committee, NLSIU and Centre for Women and the Law, NLSIU
- **Repeat Exam Facilitator**, Civil Procedure Code – I
- **Library Representative**, Batch of 2022 (July 2019 – June 2022)
- **Member**, Academic Support Initiative, NLSIU
- **Project Guide**, 1<sup>st</sup> Year, B.A. LL.B. (Hons.) students, Academic Support Programme, NLSIU
- **Co-opted Member**, Academic Support Programme, NLSIU

### INTERNSHIPS

- Human Rights Law Network, New Delhi
- Chambers of M.C. Chaturvedi, Senior Advocate, Additional Advocate General, Allahabad High Court, Uttar Pradesh
- Chambers of Rajesh Kumar Gupta, Jaunpur District Court, Uttar Pradesh
- Chamber20A, Litigation firm at New Delhi

*Snehal*  
26/06/2024